MR. CHAIRMAN: I uphold the point of order raised by Mr. Gurupadaswamy and we will follow the convention which has been followed before. But, as a special case, I will ask Mr. Tewari to lay the Paper on the Table of the House. Yes, Mr. Tewari.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): Sir, these are bad days for Mr. Tewari. (*Interruptions*).

Report (for the year 1985) of the Comptroller and Auditor-General of India, Union Government (Commrcieal) Part-I

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (SHRI K. K. TEWARI): Sir, I beg to lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution a copy (in English and Hindi) of the Report of Comptroller and Auditor General of India for the year 1985, Union Government (Commercial) Part-I. [Placed in Library. *See* No. LT-3101/86]

MR. CHAIRMAN: You should at least say, "I am sorry.".

SHRI K. K. TEWARI: Sir, I must make it abundantly clear that I had no intention to hurt the feelings of the Member or to show any disrespect to the House.

MR. CHAIRMAN: All right. All is well that ends well! Now, Mr. Engti.

All India Services (Study Leave) Second Amendment Regulations, 1986

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI BIREN SINGH ENGTI): Sir, on behalf of Shri P. Chidambaram, I beg to lay on the Table, under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Notification G.S.R. No. 584, dated the 9th August, 1986, publishing the All India Services (Study Leave) Second Amendment Regulations, 1986. [Placed in Library. *See* No. LT-3089|86.]

REPORT AND MINUTES OF THE COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Twelfth Report of the Committee on Public Undertakings on Oil and Natural Gas Commission--Head Office, Survey and Exploration and Minutes of the sittings of the Committee relating thereto.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Central Duties of Excise (Retrospective Exemption) Bill, 1986

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Central Duties of Excise (Retrospective Exemption) Bill, 1986, as passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th August, 1986,

"The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

THE DOWRY PROHIBITION (AMENDMENT) BILL, 1986

MR. CHAIRMAN: Before we take up Special Mentions, shall we allow the Minister to move her Bill ?

SHRI LAL K. ADVANI (Madhya Pradesh): After that I would seek your permission to make a submission.

MR. CHAIRMAN: All right. Mrs. Alva.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Dowry Prohibition Act, 1961.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, I introduce the Bil.

RE: PROPOSED LEGISLATION IN PURSUANCE OF ARTICLE 249 OF THE CONSTITUTION

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr Advani.

श्री लालकृष्ण आडवाणी (मध्य प्रदेश): सभापति जी, स्पेशल मेंशन से पहले मैं सदन के बाकी बिजनेस के बारे में आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। ये तीन दिन जो बढ़ाए गए इस सत्र के, अनशेड्यूल्ड, जिसमें कोई प्रश्नोत्तर काल भी नही होता, वे प्रमुख रूप से इसलिए बढाए गए कि इस सदन ने 249 अनुच्छेद का प्रस्ताव पास किया था और उस प्रस्ताव के अधीन एक विधेयक आने वाला था। अब विधेयक का क्या हुआ, इसके बारे में मैं अपेक्षा करता था कि सरकार अधिकृत रूप से जानकारी सदन को दे। हम अखबारों से पढ़ते रहें कि इस विधेयक के बारे में फिर से विचार हो रहा है, वह बिल विण्टर सेसन में आयेगा या उस प्रस्ताव के बारे में . . . (**व्यवधान**), . . विधेयक के बारे में अभी कुछ विचार हो रहा है। यह अखबार से जानकारी मिले यह सदन के लिए उचित नहीं है। अधिकृत रूप से संसदीय कार्यमंत्री या सदन के नेता या गृहमंत्री या प्रधानमंत्री हमको सूचना दें कि इस मामले में सरकार का विचार क्या है?

सभापति जी, आपको स्मरण होगा कि प्रधान मंत्री के विदेश जाने से पहले सरकार का आग्रह था। कि चाहे एक ही दिन बचा है, उस प्रस्ताव को पास करना चाहिए क्योंकि बिल लाना है, नहीं तो पंजाब की स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। आपके कहने पर उन्होंने आग्रह छोड़ा और स्वीकार किया कि प्रधान मंत्री जी आ जाएंगे उसके बाद प्रस्ताव पास हो सकता है, उसके बाद विधेयक आ सकता है। अब पता नही क्या हो रहा है। इस बीच मे हमने अखबारों में पढ़ा कि अनुच्छेद 249 संविधान का, वह राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के अनुसार जम्मू-कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया है। मैं स्वयं इसका स्वागत करता हूं, चाहे विपक्ष के मेरे अन्य साथी इससे सहमत न हों लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है और मुझे तो खुशी होगी कि पूरा का पूरा हिन्दुस्तान का संविधान वहां पर लागू हो जाय और अनुच्छेद 370 खतम हो जाये। लेकिन मैं यह अपेक्षा अवश्य करता हूं, जब इतना महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया तो इस सदन को क्यों नहीं उसके बारे में बताया गया? यह नोटिफिकेशन 31 जुलाई को जारी हुआ है और 31 जुलाई से लेकर के आज तक तीन सप्ताह हो गए हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं जो सदन के प्रति समुचित समादर होना चाहिए सरकार का, उसको प्रतिबिम्बित नही करतीं।

इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि धारा 249 के अन्तर्गत हमने जो प्रस्ताव पास किया है, उसके बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की है या क्या कार्यवाही करने जा रही है, इसके बारे में एक विस्तृत ब्यौरा सदन के सामने सरकार रखे और यह जो राष्ट्रपति महोदय का नोटिफिकेशन है, वह भी सदन के सामने रखे।

. . . (**व्यवधान**) . . .